ICAI/012/CP&GFM/TP – 15th FC State Nodal Officers

श्री आर के गौतम,
निदेशक एवं
राज्य नोडल अधिकारी
XVth वित्त आयोग,
हिमाचल प्रदेश

विषय: 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन में हिमाचल प्रदेश राज्य के शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) का सहयोग करने का प्रस्ताव

आदरणीय महोदय,

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (ICAI) वर्ष 1949 में संसद के एक अधिनियम द्वारा अपनी स्थापना बाद से भारत में लेखा और लेखा परीक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च निकाय है। राष्ट्र निर्माण में एक भागीदार के रूप में, सार्वजनिक और सरकारी वित्तीय प्रबंधन समिति (Committee on Public & Government Financial Management – CP&GFM) के माध्यम से ICAI भी कार्यशालाओं/प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करके, स्थानीय निकायों के अधिकारियों के उपयोग के लिए ई-लर्निंग मॉड्यूल विकसित करके भारत में केंद्र और राज्य सरकारों और स्थानीय सरकार (ULBs सहित) में वित्तीय रिपोर्टिंग और प्रबंधन सुधार में शामिल है । (ई-लर्निंग मॉड्यूल https://icaitv.com/category.php?cat_id=21 पर उपलब्ध है ।)

ULBs में सुधारों को तेज करने के लिए, हाल ही में 15वें वित्त आयोग ने ULB द्वारा अनुदान प्राप्त करने के लिए प्रवेश स्तर की शर्त के रूप में पिछले वर्ष के अलेखापरीक्षित वार्षिक खातों और पिछले वर्ष से पहले वर्ष के लेखा परीक्षित खातों की ऑनलाइन उपलब्धता की सिफारिश की। इसी तरह की सिफारिशें पहले के वित्त आयोगों द्वारा भी की गई थीं; हालांकि, ULB में वित्तीय रिपोर्टिंग और प्रबंधन में सुधार से जुड़ी इन सिफारिशों को ULBs में पर्याप्त सक्षम कर्मियों की उपलब्धता और उनकी क्षमता निर्माण के अभाव में वांछित परिणाम देना बाकी है।

इस दिशा में, ICAI ने CP&GFM के माध्यम से ULBs को राज्य के शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के लिए 'Accounting & Auditing in ULBs' प्रशिक्षण कार्यक्रम / वेबिनार आयोजित करने का प्रस्ताव दिया है। इन क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को विशेष रूप से संरचित किया जाएगा ताकि ULB कर्मियों को लेखांकन, लेखा परीक्षा और राजस्व में वृद्धि से संबंधित अपने ज्ञान को अद्यतन करने का अवसर प्रदान किया जा सके। कार्यक्रम के लिए सुझाए गए विषय इसके साथ संलग्न हैं जिन्हें विशिष्ट प्रशिक्षण आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया जा सकता है। कार्यक्रम/वेबिनार क्षेत्रीय भाषा में भी आयोजित किए जा सकते हैं।

यहां, हम उल्लेख करना चाहेंगे कि हाल ही में, पंजाब राज्य के लिए एक इसी तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें पंजाब ULBs के लगभग 150 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया था। हमें उम्मीद है कि यह पहल ULB के कर्मचारियों की ज्ञान उन्नयन आवश्यकताओं को पूरा करने मददगार साबित होगी ।

"ICAI Bhawan", Indraprastha Marg,
Post Box No. 7100, New Delhi - 110 002. India
Phone: (+91) (011) 3989 3989 | **Fax:** (+91) (011) 3011 0581
Email: icaiho@icai.org | **Website:** http://www.icai.org

हमें इस संबंध में आपकी सकारात्मक प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है। हमें उम्मीद है कि इस सहयोग से ULBs और समाज को बड़े पैमाने पर फायदा होगा। किसी और स्पष्टीकरण/पूछताछ के लिए कृपया हमें संपर्क करें।

धन्यवाद,

सादर,

CA केमिशा सोनी
अध्यक्ष

CA श्रीधर मुप्पला
उपाध्यक्ष

सार्वजनिक और सरकारी वित्तीय प्रबंधन समिति
सचिवालय फोन नं.: 0120-3045985
ई-मेल: cpf.aslb@icai.in; cpf_ga@icai.in

संलग्नक: उपर्युक्त के अनुसार

"ICAI Bhawan", Indraprastha Marg,
Post Box No. 7100, New Delhi - 110 002. India
Phone: (+91) (011) 3989 3989 | **Fax:** (+91) (011) 3011 0581
Email: icaiho@icai.org | **Website:** http://www.icai.org

Proposal for jointly organising training programmes/webinars for staff of Urban Local Bodies

Theme of the Training	:	Financial Transparency and Accountability in Urban Local Bodies
Duration of the Training	:	One Day/Two Days
Targeted Participants	:	Staff associated with Finance and Accounts Sections of Urban Local Bodies
No. of participants	:	Minimum 50 participants (if physical) and no limit in virtual programmes
Faculty	:	Faculty comprises of professional experts having relevant experience in the field of accrual accounting implementation and audit in Urban Local Bodies/Government, conversion projects, etc.

प्रशिक्षण के लिए संभावित विषयों की सूची/List of tentative topics for the Training

Scenario 1 : If Double Entry Accrual Accounting System is yet to be implemented

1. स्थानीय निकायों के लिए accrual accounting	1. Accrual Accounting for Local Bodies
2. ULB में लेखा और लेखा परीक्षा प्रणाली	2. Accounting and Auditing System in ULBs
3. ULBs के खातों को cash system to double entry accrual accounting system में परिवर्तित करना	3. Conversion of accounts of ULBs from cash system to double entry accrual accounting system
3. Accrual Accounting के तहत प्रारंभिक तुलन पत्र तैयार करना	4. Preparation of Opening Balance Sheet under accrual accounting system
4. लेखांकन की accrual accounting के तहत chart of accounts का पुनर्गठन	5. Restructuring of chart of accounts under accrual system of accounting
5. कार्यान्वयन के लिए IT पैकेज का उपयोग करना	6. Implementation of double entry accrual accounting system in computerised environment

Scenario 2 : If Double Entry Accrual Accounting System has been implemented

1. लेखा सुधारों की स्थिरता	1. Lessons Learnt & Sustainability of Accounting Reforms
2. Accrual आधारित वित्तीय विवरणों की व्याख्या	2. Interpreting Accrual Based Financial Statements
3. ULBs में लेखापरीक्षा	3. Audit in Urban Local Bodies
4. IT वातावरण में ULBs का लेखा परीक्षण	4. Auditing ULBs in IT environment
5. भारत में आत्मनिर्भर नगर निकाय बनाना	5. Making Self-Sufficient and Self-Sustainable Municipal Bodies in India
6. स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानक (ASLBs)	6. Accounting Standards for Local Bodies (ASLBs)
7. स्थानीय सरकार कराधान मामले: स्थिति और अनुपालन	7. Local Government Taxation Matters: Status and Compliances
8. नागरिकों के प्रति ULBs की जवाबदेही में सुधार और नगरपालिका बजट में उनकी भागीदारी	8. Improving Accountability of ULBs towards Citizens and their participation in Municipal Budgeting
9. स्मार्ट सिटी के लिए आगे का रास्ता और म्यूनिसिपल बॉन्ड	9. Way forward for Smart Cities and Municipal Bonds

Financial Implications:

- In case of physical training programme, expenditure may be borne jointly by State Government/respective Urban Development Department and ICAI as suggested below:
  - Cost to be borne by ICAI:
    - TA/DA expenses of Faculty
    - Honorarium to Faculty
    - Background material for participants
- Cost with regard to other logistic arrangements to be borne by the State Government/ respective urban development department.
- In case of virtual training programme, there shall be no financial implications on State Government/respective Urban Development Department. In that case, all the cost pertaining to platform and honorarium to faculties shall be borne by the ICAI.